

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 673 का उत्तर

भानुपली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे परियोजना

673. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भानुपली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन और नांगल-ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है और खंड-वार पूर्ण हो चुके और चल रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पूरा होने की समय-सीमा संशोधित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;
- (ग) स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि, अब तक हुए व्यय और अनुमानित लागत वृद्धि, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;
- (घ) कुल आवश्यक भूमि/अधिगृहीत भूमि सहित भूमि अधिग्रहण की स्थिति का ब्यौरा क्या है और लंबित रहने के कारण क्या हैं;
- (ङ) क्या पर्यावरण/वन/रक्षा जैसी वैधानिक मंजूरियाँ लंबित हैं और यदि हाँ, तो उनके निपटान की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के समक्ष भूमि/मुआवजा/संरेखण/सहयोग से संबंधित कोई समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (छ) रेलवे के सामने आने वाली प्रमुख भू-क्षेत्रीय/तकनीकी चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और उनके समाधान के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ) भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किमी) नई रेल लाइन परियोजना को राज्य सरकार के साथ लागत में हिस्सेदारी के आधार पर मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश में कुल अपेक्षित 124.02 हेक्टेयर भूमि में से 82 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मौजूद भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना पर अब तक 5252 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार पर 1843 करोड़ रुपए बकाया हैं। यह अंशदान न देने से इस परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता पूरा न करने की वजह से भी इस परियोजना की प्रगति प्रभावित है। परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित है।

भारत सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार है, हालांकि इसकी सफलता हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

बिलासपुर-मनाली-लेह नई लाइन को रक्षा मंत्रालय ने सामरिक लाइन के तौर पर चिन्हित किया है। बिलासपुर-मनाली-लेह नई लाइन परियोजना (489 किमी) का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 1,31,000 करोड़ रुपए है।

नंगल डैम - ऊना - अंदौरा - दौलतपुर चौक (60 किमी) खण्ड का नंगल डैम - तलवारा - मुकेरियां न्यू लाइन परियोजना को पूरा कर लिया गया है और जनवरी, 2019 से यातायात के लिए खोल दिया गया है। दौलतपुर चौक - कार्टोली पंजाब - तलवाड़ा (52 किमी) खंड का कार्य शुरू कर दिया गया है, जो पूर्णतः/अंशतः रूप से पंजाब राज्य में पड़ता है। अब तक 2568 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹108 करोड़/वर्ष
2025-26	₹ 2716 करोड़. (25 गुना से अधिक)

2009-14 और 2014-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	-	-
2014-25	16 किमी	1.5 किमी प्रतिवर्ष

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 214 किमी लंबाई वाली 03 नई लाइनें, जिनकी लागत 17622 करोड़ रुपए है, निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 64 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक ₹8280 करोड़ का व्यय किया गया है। कार्य की स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लम्बाई (किमी में)	कमीशन की गई लम्बाई (कि.मी. में)	मार्च-2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	3	214	64	8280

पूर्णतः/अंशतः हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	नंगल डैम दौलतपुर चौक नई लाइन (61 किमी)	672

हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएँ, जिन्हें शुरू किया गया है, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (रुपए करोड़ में)
1	चंडीगढ़-बददी नई लाइन (28 किमी)	1540
2	भानुपल्लि-बिलासपुर-बेरी नई लाइन (63 किमी)	6753

पंजाब

पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और सुरक्षा कार्यों के लिए किया गया बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	225 करोड़ रुपए/वर्ष
2025-26	5,421 करोड़ रुपए (24 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल लंबाई 714 किमी की 09 परियोजनाएँ (04 नई लाइन और 05 दोहरीकरण) जिनकी लागत 21,926 करोड़ रुपये है जो पूर्णतः/अंशतः पंजाब राज्य में पड़ती हैं, योजना/स्वीकृति/क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 115 किमी की लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च 2025 तक 8,079 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। सार इस प्रकार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई	कमीशन की गई लंबाई	मार्च-2025 तक खर्च (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	04	252 किमी	64 किमी	7359
दोहरीकरण/मल्टी ट्रेकिंग	05	462 किमी	51 किमी	720
कुल	09	714 किमी	115 किमी	8,079

पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	चक्की बैंक-भरौली दोहरीकरण(3 कि.मी.)	15
2	जाखल-मानसा दोहरीकरण (45 कि.मी.)	163
3	मीरथल-भंगाला ब्यास नदी दोहरीकरण (2.5 कि.मी.)	74.17
4	अंबाला-धप्पर-चंडीगढ़ दोहरीकरण (45 कि.मी.)	338.54
5	मानसा - बठिंडा दोहरीकरण (49 कि.मी.)	216
6	अमृतसर से छहरटा दोहरीकरण (7 कि.मी.)	30.91
7	जालंधर-पठानकोट-जम्मू तवी दोहरीकरण (209 कि.मी.)	850
8	कठुआ-माधोपुर पंजाब - रावी पुल पर दोहरीकरण (2.5 कि.मी.)	257.16
9	राजपुरा-बठिंडा दोहरीकरण (173 कि.मी.)	2458.99

पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं जिन्हें शुरू किया गया है, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं .	परियोजना	लागत (रुपए करोड़ में)
1	नंगल डैम -तलवाड़ा और मुकेरियां-तलवाड़ा नई लाइन (143 किमी) का साइडिंग संबंधी कार्य शुरु करना	2018
2	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाइन (63 किमी)	6753

3	कादियां-ब्यास नई लाइन (40 किमी)	842
4	फिरोजपुर-पटी नई लाइन (26 किमी)	300
5	रामा मंडी (रमन)-मौर मंडी (मौर) तलवंडी साबो के रास्ते (29 किमी) नई लाइन	154
6	लुधियाना-किला रायपुर दोहरीकरण (19 किमी)	238
7	लुधियाना-मुल्लनपुर दोहरीकरण (21 किमी)	235
8	राजपुरा-मोहाली नई लाइन (18 किमी)	443

भारत सरकार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, हालांकि इसकी सफलता पंजाब सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	कुल अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की जाने वाली शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	फिरोजपुर पट्टी नई लाइन	166	0	166
2	अलाल-हिम्मताना कॉर्ड लाइन	20	0	20
3	कादियां-ब्यास नई लाइन	151	0	151
4	रामा मंडी (रमन) - तलवंडी साबो नई लाइन	85	0	85

फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 किमी), अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो पूर्ण रूप से पंजाब में है। इस परियोजना के लिए भूमि पंजाब राज्य सरकार द्वारा निशुल्क: सौंपी जानी थी। फिरोजपुर और तरनतारन जिलों में कुल 166 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जानी है। पूरी भूमि के लिए पंचाट मार्च-23 में प्रकाशित किया जा चुका है। हालांकि पंचाट का वितरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इस महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र परियोजना के क्रियान्वयन में देरी को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय ने अपनी स्वयं की वित्तीय सहायता से फिरोजपुर-पट्टी नई लाइन (26 किमी) को शुरू करने का निर्णय लिया है।

किसी भी रेल परियोजना की मंजूरी कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- यातायात अनुमानों और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आरंभिक और अंतिम छोर संपर्कता
- मिसिंग लिंकों का संयोजन और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्द्धन
- राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्नानुसार हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंजूरी
- बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां
- क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
